

सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी नयिम मामलों में उच्च न्यायालय की कार्यवाही पर रोक

प्रलिस के लिये:

ओवर-द-टॉप (OTT) प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया मध्यस्थ ।

मेन्स के लिये:

सूचना प्रौद्योगिकी नयिम 2021, केबल टेलीविज़न नेटवर्क (संशोधन) नयिम, 2021

चर्चा में क्यों?

सर्वोच्च न्यायालय ने सोशल मीडिया और ओवर-द-टॉप (OTT) प्लेटफॉर्म के लिये नयिमक ढाँचे की प्रभावकारिता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर वभिन्न उच्च न्यायालयों में कार्यवाही पर रोक लगा दी है ।

- ये नयिमक ढाँचे **सूचना प्रौद्योगिकी नयिम 2021** और **केबल टेलीविज़न नेटवर्क (संशोधन) नयिम 2021** द्वारा स्थापति किये गए हैं ।
- यह मामला केंद्र सरकार द्वारा वभिन्न उच्च न्यायालयों में सूचना प्रौद्योगिकी नयिमों को चुनौती देने वाले मामलों को एक आधिकारिक फेसले द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने के अनुरोध के बाद सामने आया है ।
- वभिन्न उच्च न्यायालयों के समक्ष याचिकाओं में यह दावा किया गया है किये नयिम भारत में **प्रेस की स्वतंत्रता** को **"कम और प्रतबंधित"** करते हैं ।

केबल टेलीविज़न नेटवर्क (संशोधन) नयिम, 2021:

- **परिचय:**
 - इसे **केबल टेलीविज़न नेटवर्क अधिनयिम, 1995** के प्रावधानों के अनुसार **सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय** द्वारा अधिसूचति किया गया था ।
 - केबल टेलीविज़न नेटवर्क अधिनयिम, 1995 का उद्देश्य **केबल नेटवर्क की सामग्री और संचालन को वनियमति** करना है । यह अधिनयिम 'केबल टेलीविज़न नेटवर्क के बेतरतीब ढंग से बढ़ने' की प्रवृत्त को नयितरति करता है ।
- **प्रावधान:**
 - यह **त्रसितरीय शकियत नविवरण तंत्र** का प्रावधान करता है- प्रसारकों द्वारा स्व-वनियमन, प्रसारकों के नकियों द्वारा स्व-वनियमन और केंद्र सरकार के स्तर पर एक अंतर-वभिगीय समतिद्वारा नरीक्षण ।
- **महत्त्व:**
 - यह अधिसूचना महत्त्वपूर्ण है क्योंकि यह प्रसारकों और उनके स्व-नयिमक नकियों पर जवाबदेही और ज़मिंदारी डालते हुए शकियतों के नविवरण हेतु एक मज़बूत संस्थागत प्रणाली का मार्ग प्रशस्त करती है ।
 - यह प्रसारकों और उनके स्व-नयिमक नकियों के लिये जमिंदारी और जवाबदेही का प्रावधान करती है ।
 - यह टेलीविज़न के स्व-नयिमक तंत्र द्वारा OTT कंपनियों और डिजिटल समाचार प्रकाशकों पर भी लागू किया जाएगा, जैसा कि सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दशा-नरिदेश और डिजिटल मीडिया आचार संहति) नयिम, 2021 में परकिलपति है ।

सूचना प्रौद्योगिकी नयिम, 2021:

- **परिचय:**
 - ये व्यापक रूप से **सोशल मीडिया** और **ओवर-द-टॉप (Over-The-Top-OTT) प्लेटफॉर्मों** से संबंधित हैं ।
 - इन नयिमों को **सूचना प्रौद्योगिकी (IT) अधिनयिम, 2000** की धारा 87 (2) के तहत तैयार किया गया है तथा पूर्ववर्ती सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती संस्थानों के लिये दशा-नरिदेश) नयिम, 2011 के स्थान पर लाया गया है ।
- **प्रावधान:**

- **महत्त्वपूर्ण सोशल मीडिया मध्यस्थ (SSMIs):**
 - भारत में एक अधिसूचित सीमा से अधिक पंजीकृत उपयोगकर्ताओं वाले सोशल मीडिया मध्यस्थों को SSMIs के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
 - इन मध्यस्थों/इंटरमीडियरीज़ को अतिरिक्त समयक तत्परता दिखानी होगी, जैसे- मुख्य अनुपालन अधिकारियों (चीफ कंप्लायंस ऑफिसर) की नियुक्ति, कुछ वशिष्ट परस्थितियों में अपने प्लेटफॉर्म पर सूचना के पहले ओरजिनेटर (अर्थात् जसिने सबसे पहले सूचना दी) को चहिनति करना तथा कुछ वशिष कॉन्टेंट की पहचान करने के लिये प्रौद्योगिकी-आधारित उपायों को लागू करना।
- **ऑनलाइन पब्लिशर्स का वनियमन:**
 - ये नियम ऑनलाइन पब्लिशर्स (प्रकाशक) द्वारा समाचार और समसामयिक मामलों से संबंधित सामग्री एवं क्यूरेटेड ऑडियो-वजिअल सामग्री के नयिमन हेतु एक रूपरेखा निर्धारित करते हैं।
- **बड़ी सोशल-मीडिया कंपनियों की जवाबदेही तय करना:**
 - बड़ी सोशल-मीडिया कंपनियों को अपने प्लेटफॉर्म पर उपयोगकर्ता द्वारा पोस्ट किये गए कॉन्टेंट के लिये कानूनी सुरक्षा प्राप्त नहीं होगी। अतः वे भारतीय नागरिक एवं आपराधिक कानूनों के प्रति जवाबदेह होंगी।
- **शकियात नविरण तंत्र:**
 - सभी मध्यस्थों के लिये यह अनविरय है कि वे उपयोगकर्ताओं या पीड़ितों की शकियातों के समाधान हेतु एक शकियात नविरण तंत्र उपलब्ध कराएँ।
 - प्रकाशकों हेतु स्व-नयिमन के वभिन्न स्तरों के साथ एक त्रि-स्तरीय शकियात नविरण तंत्र स्थापित करने का प्रावधान किया गया है।
- **महत्त्व:**
 - सूचना प्रौद्योगिकी नयिम, 2021 का उद्देश्य मीडिया प्लेटफॉर्म और OTT प्लेटफॉर्म के सामान्य उपयोगकर्ताओं की शकियातों के नविरण तथा समयबद्ध समाधान के लिये एक शकियात नविरण तंत्र स्थापित करना तथा शकियात नविरण अधिकारी (Grievance Redressal Officer- GRO) जो कि भारत का नवासी होना चाहिये, की मदद से उस तंत्र को सशक्त बनाना है।
 - इन नयिमों के तहत महिलाओं और बच्चों को यौन अपराधों, फेक न्यूज़ तथा सोशल मीडिया के अन्य दुरुपयोग से बचाने पर वशिष ज़ोर दिया गया है।
- **महत्त्वपूर्ण मुद्दे:**
 - ये नयिम कुछ मामलों में अधनयिम के तहत प्रत्यायोजित शक्तियों से स्वतंत्र हो सकते हैं, जैसे वे महत्त्वपूर्ण सोशल मीडिया मध्यस्थों और ऑनलाइन प्रकाशकों का वनियमन करते हैं तथा जानकारी के पहले प्रवर्तक की पहचान करने के लिये कुछ मध्यस्थों की आवश्यकता होती है।
 - ऑनलाइन सामग्री को प्रतिबंधित करने के आधार अत्यंत व्यापक हैं और ये अभवियक्ता की स्वतंत्रता को प्रभावित कर सकते हैं।
 - मध्यस्थों द्वारा अधिकृत सूचना प्राप्त करने के लिये कानून प्रवर्तन एजेंसियों से अनुरोध करने के कोई प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपाय नहीं हैं।
 - इन प्लेटफॉर्म पर सूचना के प्रथम प्रवर्तक की पहचान के लिये संदेश सेवाओं की आवश्यकता व्यक्तियों की गोपनीयता पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है।

स्रोत: हडिस्तान टाइम्स